[Shrimati Jharna Das Baidya]

suicide note, Fathima had mentioned the names of those who had subjected her to mental torture because of her religious background. Minority students are the most affected ones in all educational institutions.

The Central Government should immediately look into this issue and punish the people responsible behind this act.

Demand to solve the problem of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank account holders

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, पंजाब और महराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले से देश के लगभग 17 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, जबकि लगभग 50 लाख जनता अप्रत्यक्षत: प्रभावित है। बैंकिंग सेक्टर में हुए इस घोटाले से बैंक के प्रति अविश्वास की भावना लोगों में घर कर गयी है। यह एक विमर्शणीय राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर अनेकानेक प्रश्न उठते हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 15 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हैं और 10 लोगों की मौत भी इस मुद्दे की गंभीरता को प्रदर्शित करती है। मान्यवर, लगभग दो महीने से पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपनी ही जमापूंजी को निर्गत करवा पाने में अक्षम हैं, जबकि बैंक कर्मचारी नियत समय पर वेतनमान पा रहे हैं। अभी तक देश के केंद्रीय बैंक RBI के द्वारा किसी भी प्रकार का निराकरण नही किया गया है और न ही कोई सटीक सुझाव प्रस्तावित किया गया है, जिससे लोगों के असंतोष और डर को दूर किया जा सके, न ही सरकार द्वारा कोई संतोषजनक कदम उठाए गए हैं। सरकार जब RBI से 1 लाख 76 करोड़ रुपये ले सकती है, तो 4,000 करोड़ रुपये की राशि का बेल आउट पैकेज क्यों नही दे सकती है?

Demand to enhance the rate of assistance under the post-harvest management

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): The existing pattern of assistance under the Post Harvest Management (PHM) is very low in comparison to the norm of other activities. Most of the farmers of Odisha belong to small and marginal category. So, they are unable to derive the benefits under these components. Hence the pattern of assistance may be enhanced in PHM activities, particularly, in cold chain components.

In case of protected cultivation, assistance should be provided for raising hybrid/ high value vegetables in shade net house.

Unit cost for creation of water resources under the MIDH has been fixed at ₹125/- per cubic meter, as per the guidelines of MIDH, 2014. In the meanwhile, there has been a revision of labour rate in the State. Hence, there is a need for revising the unit cost by the MoA and FW, Government of India.